

No. 2-42A/VI/409N.—Whereas the Governor of Haryana is satisfied that land specified below is needed by the Government, at public expenses, for a public purpose, namely, for the constg. Partal to Manpura Road in tehsil and district Mohindergarh, it is hereby declared that the land described in the specification below is required for the aforesaid purpose.

This declaration is made under the provisions of section 6 of the Land Acquisition Act, 1899, all to whom it may concern and under the provisions of section 7 of the said act, the Land Acquisition Collector, Haryana, P. W. D., B. & R. Branch, Hissar/Bhiwani/District Revenue Officer-cum-Land Acquisition Collector, Narnaul or any other Special Collector, authorised by the Colonization Officer-cum-Special Land Acquisition Collector, Haryana, is hereby directed to take orders for the acquisition of the said land.

Plans of the land may be inspected in the offices of the Land Acquisition Collector, Haryana, P. W. D., B. & R. Branch, Hissar/Bhiwani, and Executive Engineer, Provincial Division, Narnaul/District Revenue Officer-cum-Land Acquisition Collector, Narnaul.

#### SPECIFICATION

Name of District	Name of Tehsil	Name of Village	Area in Acres	Khasra Nos.
Mohindergarh	Mohindergarh	Partal (39)	13.51	M. No. 73 K. No. 23, 24, 25. M. No. 72 K. No. 21/1, 21/2, 21/3, 21/4, 22, 25, 24. M. No. 87 K. No. 4, 5/1, 5/2. M. No. 88 K. No. 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4, 5, 6, 7. M. No. 89 K. No. 1, 2, 3, 6/1, 6/2, 7, 8/1, 9, 10. M. No. 90 K. No. 6/2, 6/3, 7/1, 7/2, 8, 9/1, 9/2, 10/1, 10/2, 14/1, 15. M. No. 91 K. No. 11, 20, 25/1, 25/2, 25/3. M. No. 92 K. No. 11/3, 17/4, 18/2, 18/5, 19/1, 19/2, 19/3, 19/4, 20/1, 20/2, 23, 24, 25/1, 25/2. M. No. 93 K. No. 21/1, 21/2, 21/3, 22, 23. M. No. 102 K. No. 11, 12, 13, 16, 17, 18/1, 18/2, 19, 20, 25, 24. <div style="text-align: center;">101</div> 22/1, 22/2, 21/1, 21/2, 23, 24. M. No. 103 K. No. 1, 8, 7, 9/1, 9/2, 10/1, 10/2, 13, 14, 15/1, 15/2. M. No. 104 K. No. 1/1, 1/2, 2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5, 6, 7. M. No. 106 K. No. 4, 5, 7/1, 7/2, 8, 9/1, 9/2, 10/1, 10/2, 14/1. M. No. 107 K. No. 5/2, 5/3, 6/1, 6/2. M. No. 132 K. No. 2, 3, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6. M. No. 133 K. No. 1, 2, 8/1, 8/2, 7, 6, 9, 10, 13, 14, 15.

Name of District	Name of Tehsil	Name of Village	Area in Acres	Khasra Nos.
Mohindergarh	Mohindergarh	Partal (39)	13.51	M. No. 134 K. No. 11-1, 11/2, 12, 19. K. No. 160, 169, 170, 176, 181, 139, 178, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 415, 416, 454, 455, 456, 505, 556, 555, 557, 558, 559, 567, 167.
Mohindergarh	Mohindergarh	Manpura (40)	1.54	M. No. 31 K. No. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. M. No. 32 K. No. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, No. Khasra 70. No. Khasra 569, 570, 572, 573, 574, 577.
Total			15.05	

No. 2-42A/VI/410N.—Whereas the Governor of Haryana is satisfied that land specified below is needed by the Government, at public expenses, for a public purpose, namely, for the constructing Nizampur Mangal Chaudhary Road to Dulhera via Sureli Bigapur in tehsil Narnaul, district Mohindergarh, it is hereby declared that the land described in the specification below is required for the aforesaid purpose.

This declaration is made under the provisions of section 6 of the Land Acquisition Act, 1899, all to whom it may concern and under the provisions of section 7 of the said Act, the Land Acquisition Collector, Haryana, P. W. D., B. & R. Branch, Hisar/Bhiwani/District Revenue Officer-cum-Land Acquisition Collector, Narnaul or any other Special Collector authorised by the Colonization Officer-cum-Special Land Acquisition Collector, Haryana, is hereby directed to take orders for the acquisition of the said land.

Plans of land may be inspected in the offices of the Land Acquisition Collector, Haryana, P.W.D., B. & R. Branch, Hisar/Bhiwani and the Executive Engineer, Provincial Division, Narnaul/District Revenue Officer-cum-Land Acquisition Collector, Narnaul.

#### SPECIFICATION

Name of District	Name of Tehsil	Name of Village	Area in Acres	Khasra Nos.
M/Garh	Narnaul	Pawara (296)	2.66	M. No. 44, 20, 22/1, 22/2. M. No. 47 K. No. 10, 11, 12, 13, 18/1, 18/2, 19. M. No. 48 K. No. 2, 3/1, 3/2, 4, 5, 6/1, 6/2, 7, No. 66, 422.
M/Garh	Narnaul	Sureli (285)	12.89	M. No. 18 K. No. 17, 24, 25/1, 25/2, 16. M. No. 19 K. No. 21. M. No. 24 K. No. 11, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 36/5. M. No. 25 K. No. 1, 2, 3, 7, 8, 9, 14, 15/1, 15/2, 16, 17.

Name of District	Name of Tehsil	Name of Village	Area in Acres	Khasra Nos.
M/Garh	Narnaul	Surelt (285)	12.89	M. No. 26 K. No. 5 M. No. 29 K. No. 4, 5/1, 5/2, 5/3.  M. No. 30 K. No. 1, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 25.  M. No. 31 K. No. 21, 22.  M. No. 38 K. No. 20, 21, 22.  M. No. 39 K. No. 9, 11/1, 11/2, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 25, 27.  M. No. 40 K. No. 2, 3, 6, 7, 8/1.  M. No. 50 K. No. 2, 3/1, 3/2, 4, 6.  M. No. 51 K. No. 9, 10, 12/1, 13/2, 14, 15, 16/1, 16/2, 17.  M. No. 52 K. No. 20/1, 20/2, 26, 27, 104, 116, 120, 121, 122, 1, 126, 127, 128, 129, 136, 137, 328, 329, 330, 332, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 331, 337, 125, 122, 123.
M/Garh	Narnaul	Bigopur (268)	6.93	M. No. 34 K. No. 18, 22, 23, 25, 29.  M. No. 42 K. No. 1/1, 1/2, 1/3, 9, 10, 12, 13/1, 17, 18, 24, 25.  M. No. 43 K. No. 5/1, 5/2.  M. No. 47 K. No. 4, 5/1, 5/2, 6.  M. No. 48 K. No. 10, 11, 12, 18, 19/1, 19/2, 22/2, 23/1, 23/2, 24.  M. No. 51 K. No. 28.  M. No. 52 K. No. 3, 4, 7, 15.  No. Khasra 130, 139, 141, 143, 144, 142, 597, 610, 611, 612, 118, 123, 124, 125, 127, 109, 110, 117, 128.
Total ..			22.48	

(Sd.) . . . .

Superintending Engineer,

Bhiwani Circle, P.W.D., B.&R. Branch,  
Bhiwani.

अम विभाग

आदेश

दिनांक 30 जनवरी, 1987

सं० ओ०वि०/गुडगांव/121-86/4745.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै० कैंग फार्म, खाण्डता रोड, गुडगांव, के अमिक/महा सचिव कैंग ग्रुप इम्प्लाइज यूनियन, दिल्ली रोड, एफीलियेटेड इन्टक, गुडगांव तथा प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई श्रोत्रोपिक विवाद है;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिये, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण, हरियाणा, फरीदाबाद, को नीचे विनिर्दिष्ट मामले जो कि उक्त प्रवन्धकों तथा श्रमिकों के बीच या तो विवादग्रस्त मामला/मामले हैं अथवा विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला/मामले हैं न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं :—

1. क्या श्रमिक वर्दी के हकदार है? यदि हां तो किस विवरण में?
2. क्या श्रमिक वर्ष 1984-85 का वोनस 20 प्रतिशत को दर ने लेने के हकदार है? यदि हां, तो किस विवरण में?

दिनांक 9 फरवरी, 1987

सं० ओ०वि०/एफ०डी०/177-86/5004--चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै० काई० एम० सी० ए० इन्स्टीट्यूट आफ इन्जिनियरिंग जाकीर नगर फरीदाबाद, के श्रमिक महासचिव, नान टिचिंग कर्मचारी संघ, काई० एम० सी० ए० इन्स्टीट्यूट आफ इन्जिनियरिंग, फरीदाबाद, तथा प्रवन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिये, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण, हरियाणा, फरीदाबाद, को नीचे विनिर्दिष्ट मामले जो कि उक्त प्रवन्धकों तथा श्रमिकों के बीच या तो विवादग्रस्त मामला/मामले हैं अथवा विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला है न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं :—

1. क्या वह श्रमिक जिन्हें इन्डियन की हट्टी की सुविधा उपलब्ध नहीं अनिवार की छुट्टी के हकदार है? यदि हां, तो किस विवरण में?
2. क्या सर्वश्री ए० के० चौधरी व गोबल चंद को पदभूत करना लाजायज है? यदि नहीं, तो वे किस राहत के हकदार है?
3. क्या श्री हरी शंकर प्रसाद, चौकीदार की दिनांक 11 जनवरी, 1985 में दायित्व वृद्धि बन्द करना उचित है? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है?

दिनांक 17 फरवरी, 1987

सं० ओ०वि०/भिवानी/92-86/6751--चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै० 1. हरियाणा स्टेट कोऑरेटिव सलार्ई एण्ड माकिटींग फीडबैक लि० एस० सी० ग्र० 19-20, सैक्टर 7, मध्य मार्ग, चण्डीगढ़। 2. मै० हैफड, बेकरी प्लांट, भिवानी, के श्रमिक महासचिव, हरियाणा स्टेट कोऑरेटिव माकिटींग फीडबैक लि० ग्रुप लि० कोठी चौक मुहल्ला, महेंद्रगढ़, तथा प्रवन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिये, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण, हरियाणा, फरीदाबाद, को नीचे विनिर्दिष्ट मामला जो कि उक्त प्रवन्धकों तथा श्रमिकों के बीच या तो विवादग्रस्त मामला/मामले हैं अथवा विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला/मामले हैं, न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं :—

1. क्या अनुबन्ध "क" में उल्लेखित श्रमिकों को सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है? यदि नहीं, तो वे किस राहत के हकदार है?

2. क्या संस्था के सेल्जमैन अंचर टाईम लेने के हकदार है ? यदि हां तो किस विवरण में ?
3. क्या अनुबन्ध "ख" में उल्लेखित कामगार जिनकी सेवा अवधि 240 दिन से अधिक की है रेगुलर होने के हकदार है ? यदि हां, तो किस विवरण में ;

कुलवन्त सिंह,

वित्तायुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,  
श्रम तथा रोजगार विभाग ।

अनुबन्ध "क"

1. सीता राम
2. सत्य नारायण
3. हरभजन सिंह
4. रोशन लाल
5. श्रीम प्रकाश

अनुबन्ध "ख"

1. जिले सिंह
2. रामसरूप
3. धर्मपाल
4. नन्नू राम
5. सुरेश कुमार
6. हरभजन
7. राजकिशोर
8. श्रीम प्रकाश
9. रोशन लाल
10. सत्यनारायण
11. सीता राम
12. महा सिंह

श्रम विभाग

आदेश

दिनांक 4 फरवरी, 1987

सं. प्रो. वि./कु०/33-86/5215.--चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि (1) परिवहन आयुक्त, हरियाणा, चण्डीगढ़ (2) महा प्रबन्धक, राज्य परिवहन, कैथल, के श्रमिक श्री बलबीर सिंह, पुत्र श्री मोहर सिंह, गांव व डा० चिमनी, तहसील झज्जर (रोहतक) तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इस में इस के बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है।

और चूँकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना बांछनीय समझते हैं ;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उप-धारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं० 3(44)-84-3-अम, दिनांक 18 अप्रैल, 1984, द्वारा उक्त अधिनियम, की धारा 7 के अधीन गठित अम न्यायालय, प्रम्वाना, को विवादग्रस्त या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जोकि उक्त प्रवन्धकों तथा अधिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है :—

क्या श्री बलबोर सिंह चौकीदार का नया पञ्चाट प्रमाणित तथा ठीक है ? यदि नहीं तो वह किस राहत का हकदार है ?

दिनांक 6 फरवरी 1987

सं० ओ० वि० कु०/38-86/5601.—चूँकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि (1) परिवहन आयुक्त, हरियाणा, चण्डीगढ़, (2) महा प्रबन्धक, हरियाणा राज परिवहन, कैथल, के अधिक श्री रतन सिंह देवर, पुत्र श्री जग सिंह, गांव बडां बाता, तह० नरवाना, (बीन्द) तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इस में इस के बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूँकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना बांछनीय समझते हैं ;

इस लिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उप-धारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं० 3(44)-84-3-अम, दिनांक 18 अप्रैल, 1984 द्वारा उक्त अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित अम न्यायालय, प्रम्वाना, को विवादग्रस्त या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जोकि उक्त प्रवन्धकों तथा अधिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है :—

क्या श्री रतन सिंह की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं तो वह किस राहत का हकदार है ?

दिनांक 9 फरवरी, 1987

सं० ओ० वि०/एफ०डी०/10-87/5798.—चूँकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै० कृ० आर० वि०, सेक्टर 37, मथुरा रोड, फरीदाबाद (2) शिव इण्डस्ट्रियल सिम्पूरीटी सर्विस, प्लाट नं० 445, सेक्टर 18, फरीदाबाद के अधिक श्री दीवाकर सिंह भाफत हिन्द मजदूर सभा, 29 गद्दी चौक, नीलम, फरीदाबाद तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इस के बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूँकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना बांछनीय समझते हैं ;

इस लिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उप-धारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं० 5415- 3अम 68/15254, दिनांक 20 जून, 1978 के साथ पड़ते हुए अधिसूचना सं० 11495-जी-अम 57/11245, दिनांक 7 फरवरी, 1958 द्वारा उक्त अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित अम न्यायालय फरीदाबाद को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रवन्धकों तथा अधिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है ।

क्या श्री दीवाकर सिंह की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं० ओ० वि०/पानीपत/71-85/5811.—चूँकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि (1) सचिव, हरियाणा राज्य बेजलो बोर्ड, चण्डीगढ़ (2) कार्यकारी अभियन्ता, ग्रिड कन्स्ट्रक्शन डिविजन, एच.एन.ई.डी. मथुरा रोड, करनाल, के अधिक श्री देवी राम व 10 अन्य (अनुबन्ध "क"), भाफत श्री करण सिंह, भारतीय मजदूर संघ, जा.पो. राड, करनाल तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूँकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना बांछनीय समझते हैं ;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं० 3(44)84-3-अम, दिनांक 18 अप्रैल, 1984 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित अम न्यायालय, अम्बाला को विवादग्रस्त या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है :—

क्या श्री देवी राम व 10 अन्य (अनुबन्ध “क”) श्रमिकों की छंटनी न्यायोचित तथा ठीक है? यदि नहीं, तो वे किस राहत के हकदार हैं?

अनुबन्ध “क”

क्रमांक	श्रमिक का नाम	पिता का नाम
1	श्री देवी राम	श्री रमदीर सिंह
2	श्री मोहिन्द्र सिंह	श्री प्रीत
3	श्री सेठपाल सिंह	श्री धर्म सिंह
4	श्री सतपाल सिंह	श्री मन्वतूल
5	श्री सुभाष चन्द	श्री रामचन्द्र
6	श्री राम मेहर	श्री बनवारी
7	श्री शिव चरण	श्री सीता राम
8	श्री चमन लाल	श्री जय राम
9	श्री धर्म सिंह	श्री बुन्दी सिंह
10	श्री रामफल सिंह	श्री प्रमू राम
11	श्री इन्द्रजीत	श्री लक्ष्मी चन्द

मार्फत श्री करण सिंह, भारतीय मजदूर संघ, जी.टी. रोड, पानीपत ।

सं० ओ० वि०/एफ.डो./20-87/5819.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै० परफेक्ट पेक लि०, पेपर (डिविजन), 27 एन० आई० टी० फरीदाबाद, के श्रमिक श्री रामजी शाह द्वारा भारतीय मजदूर संघ, विश्वकर्मा भवन, नीलम बाटा रोड, फरीदाबाद तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इस में इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इस के द्वारा सरकारी अधिसूचना सं० 5415-3-अम 68/15254, दिनांक 20 जून, 1978 के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं० 11495-जी-अम 57/11245, दिनांक 7 फरवरी, 1958 द्वारा उक्त अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित अम न्यायालय, फरीदाबाद, को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है :—

क्या श्री रामजी शाह की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है? यदि नहीं तो, वह किस राहत का हकदार है?

सं० ओ० वि०/एफ.डी./24-87/5826.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै० भवानी इण्डस्ट्रीज, 1/11, डी० एल० एफ०, मथुरा रोड, फरीदाबाद, के श्रमिक श्री वृज मोहन झा मार्फत एटक आफिस, मार्केट नं० 1 एन० आई० टी०, फरीदाबाद तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें झगडा वाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निदिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिये, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं० 5415-3-अम 68/15254, दिनांक 20 जून, 1978 के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं० 11495-जी-अम 57/11245, दिनांक 7 फरवरी, 1958 द्वारा उक्त अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, फरीदाबाद, को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निदिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है :—

क्या श्री वृज मोहन झा की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं तो, वह किस राहत का हकदार ?

सं० ओ० वि०/भिवानी/140-86/5833.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि (1) परिवहन श्रमिक, हरियाणा, बरडीगढ़, (2) महा प्रबन्धक, हरियाणा राज्य परिवहन, भिवानी, के श्रमिक श्री रघवीर सिंह चानक, पुत्र श्री जय करण गांव व डा० बेरी, जिला रोहतक तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इन के वाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निदिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिये, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं० 9641-1-अम 78/32573, दिनांक 6 नवम्बर, 1970 के साथ गठित सरकारी अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, रोहतक को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निदिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित है :—

क्या श्री रघवीर सिंह चानक की सेवा निवृत्ति/छाती न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

दिनांक 10 जनवरी, 1987

सं० ओ० वि०/एफ.डी./10-87/5999.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै० जेष्ठान इण्डस्ट्रीयल कॉम्प्लेक्स लि०, प्लॉट नं० 85, सेक्टर 6, फरीदाबाद, के श्रमिक श्री जयमलाल सोहन श्री आर० एल० अम, जी० डी० इण्डस्ट्री० यूनियन 1कै/16, एन० आई० टी०, फरीदाबाद तथा उनके प्रबन्धकों के मध्य इस में इन के वाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ।

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निदिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिये, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं० 5415-3-अम 68/15254, दिनांक 20 जून, 1978 के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं० 11495-जी-अम 57/11245, दिनांक 7 फरवरी, 1958 द्वारा उक्त अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, फरीदाबाद को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निदिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है :—

क्या श्री जयमलाल की सेवा समाप्त की गई है या उसने स्वयं त्यागपत्र देकर नौकरी छोड़ी है, इस बिन्दु पर निर्णय के फलस्वरूप वह किस राहत का हकदार है ?

मार० एस० अग्रवाल,  
उप-सचिव, हरियाणा सरकार,  
श्रम विभाग ।